



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 629]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जुलाई 15, 2004/आषाढ़ 24, 1926

No. 629]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 15, 2004/ASADHA 24, 1926

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 15 जुलाई, 2004

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(ब्याज दायित्व नियमितीकरण) स्कीम, 2004

का.आ. 818(अ).— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 12 के साथ पठित धारा 11 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों के नकदी-खंड (कैश सेगमेंट) में स्टॉक दलालों द्वारा संदेय रजिस्ट्रीकरण फीस की बाबत ब्याज दायित्व के नियमितीकरण के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाता है, अर्थात् :-

**\* भाप्रविबो (ब्याज दायित्व नियमितीकरण) स्कीम, 2004**

**भाग - I**

1.0 भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (अधिनियम) की धारा 11 के अधीन विनिधानकर्ताओं के हितों का संरक्षण करना और प्रतिभूति बाजार के विकास को संप्रवर्तित करना, तथा उसे ऐसे उपायों जो यह ठीक समझे द्वारा विनियमित करना भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (बोर्ड) का कर्तव्य है। उपायों में, अन्य बातों के साथ, स्टॉक दलालों, उप-दलालों आदि के कामकाज को रजिस्ट्रीकृत करने तथा विनियमित करने और फीस का उद्ग्रहण करने के लिए उपबंध हो सकेगा। इस प्रकार, अधिनियम बोर्ड को स्टॉक दलालों का रजिस्ट्रीकरण करने और विनियमन करने हेतु फीस एकत्र करने के लिए सशक्त करता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 12 के निबंधनों के अनुसार, कोई स्टॉक दलाल अधिनियम

के अधीन बनाये गये विनियमों के अनुसार बोर्ड से अभिप्राप्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की शर्तों के अधीन और उनके अनुसार ही प्रतिभूतियों में क्रय, विक्रय या व्योहार करेगा अन्यथा नहीं। धारा 12(2) में उपबंध है कि रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसी रीति में और ऐसी फीस के भुगतान पर किया जायेगा जैसा विनियमों द्वारा अवधारित किया जाये। अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा प्राप्त फीस भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की साधारण निधि में जमा की जायेगी। अधिनियम की धारा 30 के निबंधनों के अनुसार, बोर्ड, अधिसूचना द्वारा, अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बना सकेगा। ऐसे विनियमों में, अन्य बातों के साथ, स्टॉक दलाल को प्रदान किये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए अदा की जाने वाली फीस की रकम के लिए उपबंध हो सकेगा।

1.1 भाप्रविबो (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 (विनियम/विनियमों) 23 अक्टूबर, 1992 को अधिसूचित हुए थे। विनियम की अनुसूची III के साथ पठित विनियम 10 स्टॉक दलालों द्वारा संदेय रजिस्ट्रीकरण फीस को विनिर्दिष्ट करती है। विनियम में उपबंध है कि ऐसी फीस पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष संबंधी वार्षिक व्यापारावर्त (टर्नओवर) के आधार पर प्रथम पाँच वर्षों के लिए संदेय होगी। रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पाँच वित्तीय वर्षों की समाप्ति के पश्चात्, पाँच वर्षों के प्रत्येक ब्लॉक के लिए 5,000 रुपये संदेय हैं। दलाल, तथापि, बोर्ड को यह अभ्यावेदन कर रहे थे कि माँग अत्यधिक थी और व्यापारावर्त के आधार पर उसका एकत्रीकरण अयुक्तियुक्त और मनमाना था। इसलिये, बोर्ड ने दलालों द्वारा संदेय फीस के संदर्भ में "व्यापारावर्त" के निर्वचन पर विचार करने के लिए श्री आर.एस. भट्ट की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति को नियुक्त किया। भट्ट समिति ने 18 दिसम्बर, 1992 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसका संप्रेक्षण था कि रजिस्ट्रीकरण फीस के अवधारण के लिए व्यापारावर्त उचित आधार था और बोर्ड द्वारा विहित फीस का भार अयुक्तियुक्त नहीं था। इसने, तथापि, कतिपय प्रकारों के संव्यवहारों के लिए फीस की रियायती दरों की सिफारिश की थी। केंद्रीय सरकार और बोर्ड ने समिति की सिफारिशों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था। बोर्ड ने दलालों को 7 जनवरी, 1993 को भट्ट समिति द्वारा सिफारिश की गई रीति में फीस अदा करने की सूचना दी।

1.2 स्टॉक दलाल विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष फीस दायित्व का प्रतिवाद करते रहे थे। अंतिम रूप से, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने, बीएसई ब्रोकर्स फोरम बनाम भाप्रविबो (सेबी) के मामले में तारीख 01 फरवरी 2001 के अपने निर्णय द्वारा, (जैसा [2001] 30 एससीएल 31 में उल्लिखित है), अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु फीस का उद्ग्रहण करने के लिए विनियमों को और भाप्रविबो की शक्ति को मान्य ठहराया। इसने यह भी अभिनिर्धारित किया कि व्यापारावर्त फीस के उद्ग्रहण के लिए उपाय हो सकता है। इसने, तथापि, भाप्रविबो को विनियमों में आर.एस. भट्ट समिति की सिफारिशों को सम्मिलित करने का निदेश दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों की अनुपालना करते हुए, आर.एस. भट्ट समिति की सिफारिशों को सम्मिलित करते हुए 20 फरवरी 2002 को विनियम संशोधित हुए थे।

1.3 इस बीच, स्टॉक दलालों द्वारा फीस के भुगतान को प्रवृत्त करने के लिए, बोर्ड ने, 16 दिसम्बर 1998 को, भाप्रविबो (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 को संशोधित किया। इस संशोधन द्वारा इसने उपबंध किया था कि यदि स्टॉक दलाल विनियमों की अनुसूची III के पैरा 1 तथा 2 के अनुसार फीस विप्रेषित करने में असफल रहता है, तो वह विलम्ब के प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज अदा करने का दायी होगा।

2.0 यह संप्रेक्षण दिया गया है कि रजिस्ट्रीकरण फीस के भुगतान में व्यतिक्रम हुए हैं। व्यतिक्रमों की पृष्ठभूमि देकर, बोर्ड ने स्कीम पुरःस्थापित करने का विनिश्चय किया है, अर्थात्, भाप्रविबो (ब्याज दायित्व नियमितीकरण) स्कीम, 2004 (स्कीम) स्टॉक एक्सचेंजों के नकदी-खंडों में स्टॉक दलालों को एकबारगी अवसर उपलब्ध कराने में समर्थ बनाने के लिए उनके व्यतिक्रमों का नियमितीकरण करने के लिए। इसलिये, भाप्रविबो (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 के विनियम 10 तथा अनुसूची III के साथ पठित अधिनियम की धारा 11 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड एतद्वारा स्कीम अर्थात् भाप्रविबो (ब्याज दायित्व नियमितीकरण) स्कीम, 2004 को पुरःस्थापित करता है। स्कीम के अधीन, यदि व्यतिक्रमी दलाल फीस की पूर्ण बकाया मूल रकम अदा करता है, यदि कोई हो, और नियमितीकरण कालावधि के दौरान बकाया ब्याज का 20%, तो उससे बकाया ब्याज का बाकी 80% अदा करना अपेक्षित नहीं होगा।

2.1 यह स्पष्ट किया जाता है कि स्कीम की समाप्ति के पश्चात्, दलाल जिसके बोर्ड के प्रति बकाया रजिस्ट्रीकरण फीस दायित्व हों पूर्ण बकाया रकम अदा करने का दायी होगा, जिसमें ब्याज सम्मिलित है, विनियमों के अनुसार और अधिनियम तथा उसके अधीन विरचित विनियमों के अधीन यथा अनुज्ञेय समुचित प्रवर्तन कार्रवाई के लिए भी दायी होगा। आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि विनियमों के विनियम 27 के निबंधनों के अनुसार, स्टॉक दलाल, जो विनियमों की अनुसूची III के अनुसार फीस अदा करने में असफल रहता है, भाप्रविबो (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002 में यथा विनिर्दिष्ट कार्रवाई के लिए दायी है, जिसमें रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन या रद्दकरण सम्मिलित है। इसके अलावा, ऐसे व्यक्ति अधिनियम की धारा 24 के अधीन अभियोजन के लिए भी दायी हो सकेंगे।

3.0 स्कीम के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

3.1 **ब्याज दायित्व नियमितीकरण :** स्कीम के अधीन, स्टॉक दलाल जिनके 1 अक्टूबर 2004 को बकाया फीस दायित्व (मूल राशि और / या ब्याज) हैं, विनियमों के अनुसार, मूल राशि की पूर्ण बकाया रकम अदा कर सकेंगे, यदि कोई हो, उस तारीख तक को बकाया ब्याज के 20% के साथ। स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट "नियमितीकरण कालावधि" के दौरान पूर्वोक्त रकमों के भुगतान पर, स्टॉक दलाल उस तारीख को बकाया ब्याज के बाकी 80% का भुगतान करने के लिए दायी नहीं होंगे।

3.2 **नियमितीकरण कालावधि :** नियमितीकरण कालावधि 15 अक्टूबर 2004 को प्रारंभ होगी और 15 नवम्बर 2004 को समाप्त होगी (दोनों दिन सम्मिलित) ।

3.3 **भुगतान की रीति :** इस स्कीम के अधीन संदेय रकम मुंबई में संदेय "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड" के पक्ष में जारी बैंकर चेक या मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में अदा की जायेगी । बैंकर चेक या मांगदेय ड्राफ्ट 15 अक्टूबर 2004 और 15 नवम्बर 2004 के बीच नीचे दिये गये पते पर पहुँच जाना चाहिये :

" भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड  
फीस कक्ष, बाजार मध्यवर्ती रजिस्ट्रीकरण एवं पर्यवेक्षण विभाग  
29वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर  
कफ परेड, मुंबई - 400 005 "

भुगतान करते समय, स्टॉक दलाल :

(i) अपनी रजिस्ट्रीकरण संख्या या पहले के दलाल(दलालों) की रजिस्ट्रीकरण संख्या(संख्याएँ) जिसके(जिनके) लिए भुगतान किया जाता है उत्कथित करेगा ;

(ii) अपना नाम या पहले के दलाल(दलालों) का(के) नाम जिसके(जिनके) लिए भुगतान किया जाता है उत्कथित करेगा ; और

(iii) मूल राशि तथा ब्याज हेतु और अपने स्वयं के दायित्वों या पहले के दलाल(दलालों) के दायित्वों हेतु भुगतान के आँकड़े उपदर्शित करेगा ।

3.4 फीस दायित्व की संगणना विनियम में विनिर्दिष्ट रीति में की जायेगी, व्यापारावर्त आँकड़ों के आधार पर, जो एक्सचेंजों द्वारा बोर्ड को विहित फॉर्मेट (भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के 30 सितंबर 2002 के परिपत्र के संलग्नक 'ग') में उपलब्ध कराये गये हैं। बकाया फीस दायित्व के अवधारण के लिए अपेक्षित स्टॉक दलालों की बाबत व्यापारावर्त आँकड़ों को अभिलिखित करने की रीति इस स्कीम के भाग II में उपबंधित है।

3.5 स्कीम के ब्यौरे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के वेबसाइट [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in) पर उपलब्ध हैं और स्टॉक एक्सचेंजों के पास भी।

3.6 स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, के लिए स्टॉक दलाल सुश्री अनिता केंकरे, उप महाप्रबंधक / श्री यू. वेणुगोपाल, सहायक महाप्रबंधक, फीस कक्ष, बाजार मध्यवर्ती रजिस्ट्रीकरण एवं पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, 29वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कफ परेड, मुंबई - 400 005, दूरभाष : 22164428/29/38/39 से संपर्क कर सकते हैं।

## भाग II

## व्यापारावर्त आँकड़ों को अभिलिखित करने की रीति

1. फरवरी 2001 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुसरण करते हुए, बोर्ड ने विनियम का संशोधन किया है और परिपत्रों को जारी करते हुए रजिस्ट्रीकरण फीस का अवधारण करने से संबंधित कई मुद्दों को समय समय पर स्पष्ट किया है। आँकड़ों की समग्रता सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने विनिर्दिष्ट फॉर्मेट (भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के तारीख 30 सितंबर 2002 के परिपत्र के संलग्नक ग) में आँकड़ों का एक्सचेंज प्रमाणन भी विनिर्दिष्ट किया है।
2. सुसंगत वर्षों के लिए सभी दलालों, भूतपूर्व और वर्तमान, की बाबत व्यापारावर्त आँकड़ा अभिप्राप्त करने के लिए बोर्ड ने आगे तेजी से कार्रवाई की है ताकि स्टॉक दलालों के रजिस्ट्रीकरण फीस दायित्व का निर्धारण करने में यह समर्थ हो सके। बोर्ड द्वारा एक्सचेंजों को भी सूचित किया गया कि वे उनके स्वयं के अभिलेखों और / या स्टॉक दलालों द्वारा एक्सचेंज को प्रस्तुत किये गये लेखापरीक्षकों के प्रमाणपत्र के आधार पर समय-सीमा के भीतर प्रत्येक स्टॉक दलाल के व्यापारावर्त आँकड़े प्रस्तुत करें। एक्सचेंजों को सूचित किया गया कि वे अपने स्वयं के अभिलेखों के आधार पर सकल व्यापारावर्त आँकड़े प्रस्तुत करें, यदि स्टॉक दलाल व्यापारावर्त आँकड़े प्रस्तुत नहीं करते हैं, पर्याप्त सूचना दिये जाने और सबद्ध स्टॉक दलाल को यह सूचित किये जाने के पश्चात् कि वे फीस की रियायती दरों के लिए पात्र नहीं होंगे और यह कि बोर्ड को एक्सचेंजों द्वारा सूचित सकल व्यापारावर्त पर 0.01% की सपाट दर उद्गृहीत की जायेगी। इसलिए, वे स्टॉक दलाल, जिन्होंने एक्सचेंजों को व्यापारावर्त की रिपोर्ट आँकड़ों सहित नहीं दी और एक्सचेंज ने अपने स्वयं के अभिलेख के आधार पर व्यापारावर्त आँकड़े प्रस्तुत किये, फीस की किसी भी रियायती दर के हकदार नहीं होंगे।
3. उपर्युक्त नीति के अनुसार, बोर्ड एक्सचेंजों से व्यापारावर्त आँकड़े प्राप्त करता रहा है और उन्हें अभिलिखित करता रहा है। इसलिए, आँकड़ों में और संशोधन करने की अनुज्ञा नहीं है, भले ही स्टॉक दलाल इस अंतिम चरण में लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की इच्छा रखता हो, या फिर एक्सचेंज अपने स्वयं के आँकड़ों को संशोधित करना चाहता हो। यह उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतया आवश्यक है कि आँकड़ा संशोधन प्रक्रिया हमेशा के लिए जारी नहीं रहती है। चूँकि एक्सचेंजों / स्टॉक दलालों को पहले से ही पर्याप्त सूचनाएँ / अनुस्मारक भेजे गये हैं और बोर्ड एक्सचेंज द्वारा सम्यक् प्रमाणित नवीनतम व्यापारावर्त आँकड़ों को अभिलिखित कर रहा है, बोर्ड किसी भी अभ्यावेदन / शिकायत पर विचार नहीं करेगा।

4. अब तक प्राप्त आँकड़ों को अभिलिखित करने के पश्चात्, बोर्ड लुप्त आँकड़ों का पता लगायेगा और एक्सचेंजों को इसकी सूचना देगा। बदले में एक्सचेंजों से अपेक्षित होगा कि वे विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर, उनके अभिलेखों में यथा उपलब्ध, लुप्त आँकड़ों की रिपोर्ट दें, स्टॉक दलालों को इस चरण में आँकड़े प्रस्तुत करने का कोई हवाला दिये बिना। ऐसे आँकड़ों, यदि प्राप्त हों, को अभिलिखित किया जायेगा। तत्पश्चात् बोर्ड स्टॉक दलालों के यथार्थ फीस दायित्व का अवधारण करेगा और एक्सचेंजों को इसकी सूचना देगा। उपर्युक्त क्रियाकलापों के लिए समय अनुसूची निम्नानुसार होगी :

क्र. सं.	क्रियाकलाप	समय सीमा
1	बोर्ड द्वारा एक्सचेंजों को 2003-04 तक के सुसंगत व्यापारावर्त वर्षों के लिए आँकड़ों के अंतर अग्रेषित करना	19.07.2004
2	एक्सचेंजों द्वारा अपने स्वयं के अभिलेखों के अनुसार आँकड़ों के अंतरों की बाबत व्यापारावर्त आँकड़े प्रस्तुत करना	02.08.2004
3	बोर्ड द्वारा उपर्युक्त (2) के अनुसार एक्सचेंजों द्वारा अग्रेषित व्यापारावर्त आँकड़ों को अभिलिखित करना	18.08.2004
4	बोर्ड द्वारा एक्सचेंजों को स्टॉक दलालों की बाबत फीस दायित्व विवरणों को अग्रेषित करना	03.09.2004
5	एक्सचेंज द्वारा सूचित व्यापारावर्त या फीस दायित्व की संगणना में पाये गये फर्क, यदि कोई हो, की रिपोर्ट एक्सचेंजों द्वारा बोर्ड को देना	17.09.2004
6	बोर्ड द्वारा उपर्युक्त 5 के अनुसार एक्सचेंजों की रिपोर्टों के आधार पर सुधार, यदि कोई हो, करना	01.10.2004
7	बोर्ड द्वारा उपर्युक्त 6 के अनुसार सुधार करने के पश्चात्, बकाया फीस दायित्व के विवरण एक्सचेंजों को अग्रेषित करना	08.10.2004
8	नियमितीकरण कालावधि	15 अक्टूबर 2004 से 15 नवंबर 2004

#### 5. विनिर्दिष्ट संव्यवहार

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के तारीख 30 सितंबर 2002 के परिपत्र के अनुसार, विनिर्दिष्ट संव्यवहारों (अनिवार्य वायदा, उलटाव बदला, उलटाव 6ए/7ए संव्यवहार) को रजिस्ट्रीकरण फीस के उद्ग्रहण के प्रयोजन के लिए दलाल के व्यापारावर्त में शामिल नहीं किया जाना है यदि ऐसे संव्यवहार एक्सचेंजों द्वारा बनाये रखे गये प्रत्येक दलाल के कुल व्यापारावर्त आँकड़ों का भाग हैं। यह परिपत्र वहाँ तक संशोधित हो जायेगा कि ऐसे विनिर्दिष्ट संव्यवहारों को यथास्थिति, या तो एक्सचेंज के अभिलेखों अथवा दलाल द्वारा

उपलब्ध कराये गये लेखापरीक्षक के प्रमाणपत्र, या एक्सचेंज द्वारा पहले ही की गयी लेखापरीक्षा के आधार पर शामिल नहीं किया जा सकता है।

## 6. सहायक संस्थाओं द्वारा संदेय रजिस्ट्रीकरण फीस

6.1 विनियमों के अनुसार, प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों की सदस्यता प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए बनी एक्सचेंजों की सहायक संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के रजिस्ट्रीकरण फीस अदा करें। तथापि, उनसे यह अपेक्षित नहीं कि वे ऐसे उप-दलालों द्वारा उपदर्शित व्यापारावर्त पर फीस अदा न करें, जिन्होंने मूल एक्सचेंज में स्टॉक दलालों के तौर पर प्रथम पाँच वर्षों और पाँच वर्षों के ब्लॉक के लिए फीस अदा की है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत फीस के लिए दायी व्यापारावर्त का अवधारण करना कठिन है। कठिनाइयों को दूर करने के लिए और सहायक संस्थाओं के फीस दायित्व का अवधारण करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, एक आसान और साम्यापूर्ण दृष्टिकोण अपनाये जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। इस साम्यापूर्ण दृष्टिकोण के अंतर्गत सहायक दलाली कंपनी दूसरे वर्ष से लेकर पाँचवें वर्ष तक इसके सकल व्यापारावर्त के 20% पर सामान्य दर पर फीस अदा करने की दायी होगी। सहायक संस्थाओं के पास विकल्प होगा कि वे विनियम में विहित रीति में या साम्यापूर्ण दृष्टिकोण के अनुसार फीस अदा करें।

6.2 इस वैकल्पिक दृष्टिकोण का प्रस्ताव ऐसी सभी सहायक संस्थाओं को किया जा रहा है सिवाय इंटर कनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज (आइएसई) द्वारा स्थापित सहायक संस्था को छोड़कर, जो 18 नवंबर 1998 को रजिस्ट्रीकृत हुआ था और इसकी सहायक संस्था 24 फरवरी 2000 को रजिस्ट्रीकृत हुई थी। इसलिए, आइएसई के किसी भी व्यापारी / व्याहारी ने उप-दलाल बनने के समय पाँच वर्षों की कालावधि पूरी नहीं की थी। आइएसई सिक्योरिटीज एण्ड सर्विसेज लि. (आइएसएसएल), आइएसई की सहायक संस्था, से यह अपेक्षित होगा कि वह उप दलालों द्वारा दावा की गयी आदत-रियायतों के अध्यधीन सहायक संस्था के पूरे व्यापारावर्त पर फीस अदा करे।”

[फा. सं. भाप्रविबो/एमआइआरएसडी/डीओआर-1/15292/2004]

ज्ञानेन्द्र नाथ बाजपेयी, अध्यक्ष

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA****NOTIFICATION**

Mumbai, the 15th July, 2004

**Securities and Exchange Board of India (Interest Liability Regularisation) Scheme, 2004**

**S.O. 818(E).**— In exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (k) of sub-section (2) of section 11 read with section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) the Board hereby makes the following scheme for regularisation of interest liability in respect of registration fees payable by stock brokers in the cash segments of Stock Exchanges under the SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992, namely:-

**“ SEBI (Interest Liability Regularisation) Scheme, 2004****Part - I**

1.0 Under section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (the Act) it is the duty of the Securities and Exchange Board of India (the Board) to protect the interests of investors and to promote the development of, and to regulate the securities market by such measures as it thinks fit. The measures may provide, inter alia, for registering and regulating the working of stock brokers, sub-brokers etc. and levying fees. Thus, the Act empowers the Board to collect fees for registering and regulating the stock brokers. Further, in terms of section 12 of the Act, no stock broker shall buy, sell or deal in securities except under, and in accordance with the conditions of a certificate of registration obtained from the Board in accordance with the regulations made under the Act. Section 12 (2) provides that every application for registration shall be in such manner and on payment of such fees as may be determined by regulations. The fees received by the Board under the Act are credited to the Securities and Exchange Board of India General Fund. In terms of section 30 of the Act, the Board may, by notification, make regulations to carry out the purposes of the Act. Such regulations may provide, inter alia, for the amount of fees to be paid for certificate of registration granted to a stock broker.

1.1 The SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992 (the Regulations) were notified on October 23, 1992. Regulation 10 read with Schedule III of the Regulations specifies the registration fees payable by the stock brokers. The Regulations provide that such fees shall be payable for first five years based on the annual turnover relating to the preceding financial year. After expiry of five financial years from the date of registration, Rs. 5,000 is payable for every block of five years. The brokers, however, had been representing to the Board that the demand was excessive and the collection of same based on turnover was unreasonable and arbitrary. Therefore, the Board appointed an Expert Committee under the Chairmanship of Shri R. S. Bhatt to look into the interpretation of 'turnover' in the context of fees payable by brokers. The Bhatt Committee submitted its report on December 18, 1992. It observed that the turnover was a fair basis for determination of registration fees and the incidence of fees prescribed by Board was not unreasonable. It, however, recommended concessional rates of fees for certain types of transactions. The Central Government and the



Board accepted the recommendations of the Committee in principle. The Board advised the brokers on January 7, 1993 to pay fees in the manner recommended by the Bhatt Committee.

1.2 The stock brokers had been contesting the fees liability before various High Courts. Finally the Hon'ble Supreme Court of India, vide its judgement dated February 01, 2001 in the matter of BSE Brokers Forum vs. SEBI, (as reported in [2001] 30 SCL 31), upheld the Regulations and the power of SEBI to levy fees for carrying out the purposes of the Act. It also held that turnover can be the measure for levy of fees. It, however, directed SEBI to incorporate the recommendations of the R. S. Bhatt Committee in the Regulations. In compliance with the directions of the Hon'ble Supreme Court, the Regulations were amended on February 20, 2002 by incorporating the recommendations of the R. S. Bhatt Committee.

1.3 In the mean time, in order to enforce payment of fees by the stock brokers, the Board, on December 16, 1998, amended the SEBI (Broker and Sub Broker) Regulations, 1992. By this amendment it was provided that if a stock broker fails to remit fees in accordance with paragraph 1 and 2 of Schedule III of the Regulations, he shall be liable to pay interest at the rate of 15% per annum for each month of delay or part thereof.

2.0 It has been observed that defaults have occurred in payment of registration fees. Given the background of defaults, the Board has decided to introduce a scheme, namely, SEBI (Interest Liability Regularisation) Scheme, 2004 (the Scheme) to provide a one time opportunity to enable the stock brokers in the Cash segments of stock exchanges to regularize their defaults. Therefore, in exercise of the powers under Section 11 of the Act read with Regulation 10 and Schedule III of the SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992, the Board hereby introduces the Scheme viz. SEBI (Interest Liability Regularisation) Scheme, 2004. Under the Scheme, if the defaulting broker pays the entire outstanding principal amount of fee, if any, and 20% of the outstanding interest during the regularization period, he will not be required to pay the balance 80% of outstanding interest.

2.1 It is clarified that after the expiry of the scheme, a broker having outstanding registration fee liabilities towards the Board shall be liable to pay entire outstanding amount, including interest, as per the Regulations and shall also be liable for appropriate enforcement action as permissible under the Act and the Regulations framed thereunder. It is further clarified that in terms of regulation 27 of the Regulations, a stock broker, who fails to pay fees as per schedule III of the Regulations, is liable for action as specified in the SEBI (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002, including the suspension or cancellation of certificate of registration. Besides, such persons may also be liable for prosecution under section 24 of the Act.

3. 0. The details of the Scheme are as under:

3.1. **Interest Liability Regularisation:** Under the Scheme, the stock brokers who have outstanding fee liabilities (principal and / or interest) as on 1<sup>st</sup> October 2004, as per the Regulations, may pay the entire outstanding amount of principal, if any, together with 20% of the outstanding interest as on that date. On payment of the aforesaid amounts during the "Regularisation Period" specified under the Scheme, the stock brokers shall not be liable for payment of the balance 80% of the outstanding interest on that date.

3. 2 **Regularisation Period:** The regularization period shall commence on 15<sup>th</sup> October 2004 and end on 15<sup>th</sup> November 2004 (both days inclusive).

3. 3 **Mode of Payment:** The amount payable under this Scheme shall be paid by way of a Banker's Cheque or Demand Draft drawn in favour of "Securities and Exchange Board of

India" payable at Mumbai. The Banker's Cheque or Demand Draft must reach between 15<sup>th</sup> October 2004 and 15<sup>th</sup> November 2004 at the address given below:

*"Securities and Exchange Board of India  
Fee Cell, Market Intermediaries Registration and Supervision Department  
29<sup>th</sup> Floor, World Trade Centre  
Cuffe Parade, Mumbai- 400005."*

While making payment, the stock broker shall:

- (i) quote his registration number or the registration number(s) of the erstwhile broker(s) for whom the payment is made;
- (ii) quote his name or the name(s) of erstwhile broker(s) for whom the payment is made; and
- (iii) indicate the break up of the payment towards principal and interest and towards its own liabilities or the liabilities of erstwhile broker(s).

3.4 The fee liability shall be computed in the manner specified in the Regulations, based on the turnover data, as provided by the Exchanges to the Board in the prescribed format (Annexure 'C' of the SEBI Circular 30<sup>th</sup> September 2002). The manner of taking on record the turnover data in respect of stock brokers required for determination of outstanding fee liability is provided in Part – II of this Scheme.

3.5 The details of the Scheme are available on the website of SEBI at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in) and also with the stock Exchanges.

3.6 For clarifications, if any, the stock broker may contact Ms. Anita Kenkare, Deputy General Manager / Mr. U. Venugopal, Assistant General Manager, Fee Cell, Market Intermediaries Registration and Supervision Department, Securities and Exchange Board of India, 29<sup>th</sup> Floor, World Trade Centre, Cuffe Parade, Mumbai- 400005, Tel: 22164428/29/38/39.

## Part - II

### Manner of taking Turnover Data on Record

1. Following the Hon'ble Supreme Court judgement in February 2001, the Board has amended the Regulations and from time to time clarified several issues relating to determination of registration fees through issue of circulars. The Board has also specified the Exchange certification of the data in specified format (Annexure 'C' of the SEBI Circular dated September 30, 2002) in order to ensure integrity of the data.

2. The Board has followed up vigorously to obtain turnover data in respect of all brokers, past and present, for the relevant years in order to enable it to assess registration fee liability of the stock brokers. Exchanges were also advised by the Board to submit the stock broker wise turnover data within a time frame based on their own records and/ or the auditors' certificate submitted by the stock brokers to the Exchange. The Exchanges were advised to submit gross turnover data based on their own records, if the stock brokers do not submit turnover data, after giving sufficient notice and intimating the stock brokers concerned that they would not be eligible for concessional rates of fee and that fee at a flat rate of 0.01% would be levied on the gross turnover reported by the Exchanges to the Board. Therefore, those stock brokers, who did not report turnover with break up to Exchanges and the Exchange submitted the turnover data based on its own records, will not be entitled to any concessional rates of fees.

3. In accordance with the above policy, the Board has been receiving turnover data from the Exchanges and taking them on record. No further data revisions would, therefore, be permitted - even if a stock broker wishes to submit an auditor certificate at this late stage, or, if the Exchange desires to revise its own data. This measure is absolutely necessary to ensure that the process of data revision does not remain open ended for ever. As sufficient advance notices and reminders have been sent to the Exchanges / stock brokers and the Board is taking on record the latest turnover data duly certified by the Exchange, no representations/ complaints would be entertained by the Board.

4. After taking the data received so far on record, the Board would identify the missing data and advise the same to the Exchanges. The Exchanges, in turn, would be required to report the missing data as available in their records within a specified time frame, without making any reference to the stock brokers to submit the break-up at this stage. Such data, if received, would be taken on record. Thereafter, the Board would determine the exact fee liability of the stock brokers and advise the same to the Exchanges. The time schedule for the above activities shall be as follows:

Sl. No.	Activity	Time Frame
1	The Board to forward the data gaps for the relevant turnover years up to 2003-04 to the Exchanges	19.07.2004
2	Exchanges to submit the turnover data in respect of data gaps as per their own records	02.08.2004
3	The Board to take on record the turnover data forwarded by the Exchanges as at (2) above	18.08.2004
4	The Board to forward the fee liability statements in respect of stock brokers to the Exchanges	03.09.2004
5	Exchanges to report back discrepancies noted, if any, from the turnover reported by the Exchange or in the fees liability computation, to the Board	17.09.2004
6	The Board to make corrections, if any, based on reports of the Exchanges as at 5 above	01.10.2004
7	The Board to forward outstanding fee liability statements to Exchanges, after correction as at 6 above	08.10.2004
8	Regularisation Period	15 <sup>th</sup> October 2004 to 15 <sup>th</sup> November 2004

### 5. Specified Transactions

As per SEBI circular dated September 30, 2002, the specified transactions (compulsory carry forward, reversal badla, reverse 6A/7A transactions) are not to be included in the turnover of the broker for the purpose of levy of registration fees if such transactions form a part of the broker-wise total turnover figures maintained by the Exchanges. This circular stands modified to the extent that such specified transaction can be excluded based on either Exchange's records or auditors' certificate provided by the broker, or the audit already done by the Exchange, as the case may be.

**6. Registration Fees Payable by Subsidiaries**

6.1 As per the regulations, the subsidiaries of the Exchanges floated for the purpose of seeking membership of major stock Exchanges are required to pay registration fees to SEBI. However, they are not required to pay fees on the turnover effected by the sub-brokers who have paid fees for first five years and a block of five years as stock brokers on the parent Exchange. Under this approach, it is difficult to determine the turnover liable to fees. In order to resolve the difficulties and to simplify the process of determination of fee liability of subsidiaries, a simple and equitable approach is being offered. Under this equitable approach, the subsidiary broking company would be liable to pay fees at normal rate on 20% of its gross turnover from 2nd year to 5th year. The subsidiaries would have an option to pay fees in the manner prescribed in the regulations or as per the equitable approach.

6.2 This alternative approach is being offered to all such subsidiaries except the subsidiary floated by Inter Connected Stock Exchange (ISE), which was registered on November 18, 1998 and its subsidiary was registered on February 24, 2000. Hence, none of the traders/dealers of ISE had completed the five year period at the time of becoming sub-brokers. ISE Securities & Services Ltd. (ISSSL), the subsidiary of ISE, would be required to pay fees on full turnover of the subsidiary subject to jobbing concessions claimed by the sub-brokers."

[F. No. SEBI/MIRSD/DOR-I/15292/2004]

G.N. BAJPAI, Chairman